

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3207
16 मार्च, 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का विकास

3207. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

श्री अनंतकुमार हेगडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के इस्पात विनिर्माण उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाने के कारण वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस्पात क्षेत्र को घरेलू क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय इस्पात क्षेत्र की सक्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री

श्री विष्णु देव साय

(क) और (ख): भारत में इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णय निजी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उपक्रमों के रूप में प्रत्येक निवेशकों द्वारा भारत सरकार पर निर्भर न करते हुए अपने वाणिज्यिक विवेक तथा अपनी इक्विटी और ऋण से बाजार गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। इस्पात मंत्रालय इस्पात निवेशकों तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के बीच एक सुविधादाता एवं समन्वायकर्ता की भूमिका निभाता है।

(ग) और (घ): देश में इस्पात उद्योग की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए लौह अयस्क का पर्याप्त उत्पादन होता है। तथापि, गोवा और उड़ीसा राज्यों में लीज नवीनीकरण तथा कर्नाटक राज्य में खनन लीजों के निरस्तीकरण के संबंध में उच्च तम न्यायालय के निर्णयों के कारण लौह अयस्क की क्षेत्रीय स्तर पर कमी हुई है। विगत कुछ वर्षों के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन और सूचित खपत निम्न अवत है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	सूचित खपत
2011-12	168.58	100.57
2012-13	136.62	103.40
2013-14 (पी)	152.43	110.50

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो)

(इ) एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। तथापि, सरकार ने इस्पात उद्योग को वैश्विक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए निम्न लिखित कदम उठाए हैं:

- (i) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के बीच समन्वयन और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) स्थापित किया गया है। इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलम्बश करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस्पात उत्पादन क्षमताएं शीघ्र ही स्थापित होंगी तथा लागत एवं समय वृद्धि में कमी आयेगी।
- (ii) घरेलू इस्पात उद्योग हेतु घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने और लौह अयस्का की उपलब्धता सुधारने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है तथा लौह अयस्कह पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्कक किया गया है।
